



8.2% जीडीपी: भारत की विकास गाथा मजबूत हुई

मजबूत जीडीपी वृद्धि, स्थिर मुद्रास्फीति, ज़ोरदार उत्पादन और बढ़ते निर्यात ने भारत के विकास में अपना सहयोग दिया है

28 नवंबर, 2025

मुख्य बिंदु

- वास्तविक जीडीपी में दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में 8% की वृद्धि दर्ज की गई
- अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) घटकर 0.25% हो गया, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला की साल-दर-साल की सबसे कम मुद्रास्फीति है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने सितंबर 2025 में साल-दर-साल 4.0% की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि से प्रेरित है।
- श्रम बल भागीदारी दर छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो अक्टूबर 2025 में 55.4% तक पहुंच जाएगी।
- भारत का संचयी निर्यात (माल और सेवाएं) अप्रैल-अक्टूबर 2024 की तुलना में अप्रैल-अक्टूबर 2025 में 4.84% बढ़ा

परिचय

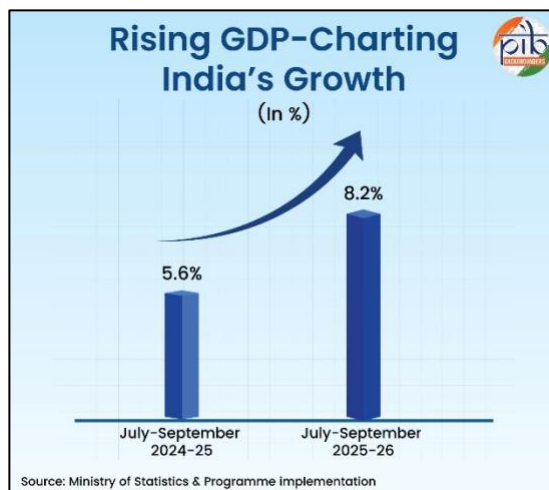
भारत की आर्थिक उन्नति वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। इसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वर्तमान विकास निर्णायक नीति निर्माण, संरचनात्मक सुधारों और भारत के बढ़ते वैश्विक एकीकरण की ताकत को दर्शाता है।

विकास में तेजी के साथ भारत ने एक बार फिर वैश्विक समकक्षों को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इस वृद्धि को अनुकूल घरेलू मांग, नरम मुद्रास्फीति और उच्च श्रम बल भागीदारी से बल मिला है। घरेलू निवेश में पुनरुत्थान और मजबूत निवेशक भावना एक स्थिर और व्यापक आधार वाली अर्थव्यवस्था का संकेत है। जैसे-जैसे सुधारों की गति बढ़ती जा रही है और खपत आशावादी बनी हुई है, भारत का आर्थिक दृष्टिकोण उत्साहजनक बना हुआ है, जो सभी क्षेत्रों में निरंतर गति और विकास का संकेत देता है।

महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक : भारत की स्थिर वृद्धि

मजबूत जीडीपी वृद्धि

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) समग्र आर्थिक प्रदर्शन के प्राथमिक संकेतकों में से एक है जो देश की विस्तार दर को दर्शाता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मुद्रास्फीति के लिए समायोजित भारत की वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान 5.6% की वृद्धि दर के मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान यह वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में सांकेतिक सकल



घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.7% की वृद्धि दर देखी गई है। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 3.1% की वास्तविक जीवीए वृद्धि दर का अनुभव किया। इसी तरह द्वितीयक (8.1%) और तृतीयक क्षेत्र (9.2%) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ावा दिया है।

वित्त वर्ष 26 की अर्धवार्षिक वृद्धि

पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025-26) में वास्तविक जीडीपी ने वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही में 6.1% की वृद्धि दर की तुलना में 8% की वृद्धि दर दर्ज की। प्राथमिक क्षेत्र (2.9%) में मध्यम वृद्धि देखी गई, जबकि द्वितीयक (7.6%) और तृतीयक क्षेत्र (9.3%) में निरंतर विस्तार देखा गया।

मुद्रास्फीति में स्थिरता देखी गई

अक्टूबर 2025 में भारत की मुद्रास्फीति की गति उल्लेखनीय नरमी को दर्शाती है, जो अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों और प्रभावी मूल्य प्रबंधन उपायों को रेखांकित करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई प्रमुख मुद्रास्फीति पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 0.25% हो गई, जो वर्तमान सीपीआई श्रृंखला में दर्ज सबसे कम स्तर है। मुद्रास्फीति आरबीआई के सहिष्णुता के दायरे में बनी हुई मुद्रास्फीति में कमी आरबीआई के उस निर्णय के अनुरूप है जिसमें उसने तटस्थ रुख के साथ रेपो दर को 5.50% पर बनाए रखा है, जो मूल्य स्थिरता और विकास संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है।

यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति (सीएफपीआई) में आई तेज़ गिरावट के कारण हुई, जो अक्टूबर 2024 के मुकाबले (-)5.02 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसे तेल और वसा, सब्जियाँ, फलों, अंडों,

अनाज और अन्य उत्पादों की कीमतों में आई नरमी से बल मिला। यह रुझान जीएसटी दरों में हालिया गिरावट के सकारात्मक प्रभाव को भी दर्शाता है।

ग्रामीण मुद्रास्फीति (-)0.25 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 0.88 प्रतिशत रही, जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी नरमी का संकेत है। मुद्रास्फीति में निरंतर कमी क्रय शक्ति को सुदृढ़ करती है, वास्तविक उपभोग वृद्धि को सहारा देती है और निवेश एवं उत्पादन विस्तार को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीतिगत गुंजाइश प्रदान करती है। कुल मिलाकर, मुद्रास्फीति में नरमी आने वाली तिमाहियों में सतत, समावेशी और स्थिर आर्थिक विकास की नींव को मजबूत करती है।

भारत का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति भी अक्टूबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2025 में (-)1.21 प्रतिशत तक कम हो गई, जो खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खनिज तेल और मूल धातु निर्माण आदि सहित प्रमुख वस्तुओं की कीमतों में गिरावट को दर्शाती है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर अक्टूबर 2025 में (-)5.04 प्रतिशत तक और गिर गई, जो सितंबर 2025 में -1.99 प्रतिशत से कम है। थोक मुद्रास्फीति में यह निरंतर कमी व्यवसायों की क्रय शक्ति में मजबूती और बाजार की धारणा में सुधार का संकेत देती है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि

आईआईपी विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र में वृद्धि को मापता है, जो औद्योगिक गतिविधि की मजबूती को दर्शाता है। भारत के आईआईपी ने सितंबर 2025 में वार्षिक आधार पर 4.0 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में 4.8 प्रतिशत विस्तार से प्रेरित थी। बढ़ता आईआईपी मजबूत उत्पादन, उच्च रोजगार और मजबूत निवेश गति का संकेत देता है, जो अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पथ को मजबूत करता है।

मजबूत प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार शीर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ता विनिर्माण क्षेत्र से हैं। यह प्रदर्शन भारत के औद्योगिक आधार की मजबूती और व्यापक विकास एजेंडे में सार्थक योगदान देने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है।

- मूल धातुओं का निर्माण (12.3 प्रतिशत की वृद्धि),
- विद्युत उपकरणों का निर्माण (28.7 प्रतिशत की वृद्धि), और
- मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों का निर्माण (14.6 प्रतिशत)

उपयोग-आधारित वर्गीकरण के दृष्टिकोण से, कई श्रेणियों में सराहनीय वृद्धि दर्ज की गई। इसके शीर्ष तीन योगदानकर्ता हैं: बुनियादी ढाँचा और निर्माण वस्तुओं में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि और मध्यवर्ती वस्तुओं में सितंबर 2025 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि। प्राथमिक वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्रों में यह विविध वृद्धि मजबूत निवेश गतिविधि और सुगम उपभोग माँग, दोनों का संकेत देती है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के साथ, ये पैटर्न एक संतुलित औद्योगिक उछाल को दर्शाते हैं जो निरंतर, समावेशी आर्थिक विस्तार की नींव को मजबूत करता है।

सरकारी हस्तक्षेप से विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिला

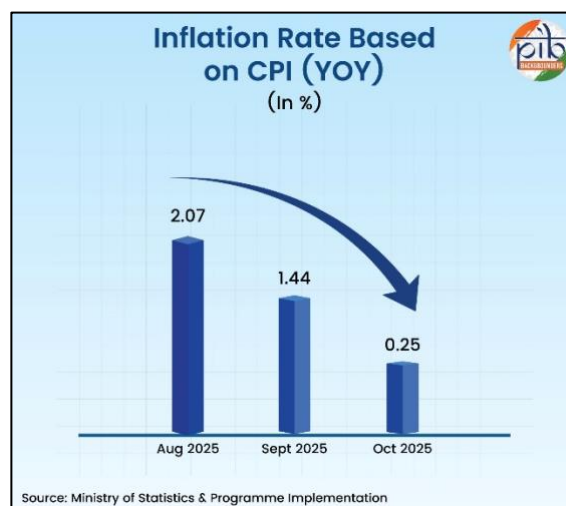
विनिर्माण क्षेत्र देश के विकास मॉडल का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभरा है, जो न केवल घरेलू माँग को पूरा कर रहा है, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति को भी मज़बूत कर रहा है। प्रमुख पहलों ने इस क्षेत्र की विकास गाथा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वर्ष 2020 में शुरू की गई उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करती है, जो बिक्री में वृद्धि से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देती है और आत्मनिर्भर भारत तथा वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ मेल खाती है।

1.97 लाख करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय और 800 से अधिक आवेदनों के साथ, इसने 1.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है, जिससे उत्पादन, निर्यात और रोज़गार में वृद्धि हुई है। यह उद्योग जगत के मज़बूत आत्मविश्वास और इसे तेज़ी से अपनाने को दर्शाता है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और जीएसटी सुधार जैसी अन्य पहलों का उद्देश्य क्षमता निर्माण में तेज़ी लाना और भारतीय विनिर्माण इकोसिस्टम को मज़बूत करना है।

मज़बूत रोजगार वृद्धि

आर्थिक विकास के लिए एक मज़बूत श्रम शक्ति अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह सभी क्षेत्रों में उत्पादन, नवाचार और उपभोग को बढ़ावा देती है। अर्थव्यवस्था का ईंधन, श्रम बाजार, अक्टूबर 2025 में भी सुगमता के उत्साहजनक संकेत दिखा रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सीडब्ल्यूएस (वर्तमान में साप्ताहिक स्थिति) में समग्र श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) अक्टूबर 2025 में 55.4 प्रतिशत तक पहुँच गई, जो जून 2025 के 54.2 प्रतिशत के मुकाबले छह महीने का उच्चतम स्तर दर्ज करती है। अन्य श्रम बाजार संकेतकों जैसे श्रमिक भागीदारी दर (52.5 प्रतिशत, जून 2025 से बढ़ रही है), महिला भागीदारी (34.2 प्रतिशत, मई 2025 के बाद से उच्चतम) और बेरोजगारी दर (सितंबर 2025 से 5.2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित) में भी सुधार देखा गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जुलाई 2025 के दौरान 21.04 लाख कुल सदस्यों की वृद्धि दर्ज की, जो जुलाई 2024 की तुलना में कुल वेतन वृद्धि में 5.55 प्रतिशत की वृद्धि है। नए ग्राहकों में यह वृद्धि रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के सफल जनसंपर्क कार्यक्रमों को दर्शाती है।



संकेतक	सितंबर 2025 (प्रतिशत में)	अक्टूबर 2025 (प्रतिशत में)
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)	52.4	52.5
बेरोजगारी की दर	5.2	5.2
महिला श्रम शक्ति भागीदारी	34.1	34.2
ग्रामीण श्रम शक्ति भागीदारी	57.4	57.8
शहरी श्रम बल भागीदारी	50.9	50.5

नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स

नौकरी जॉबस्पीक इंडेक्स भारत में वाइट कॉलर भर्ती का एक प्रमुख संकेतक है। सितंबर 2025 में इंडेक्स में वर्ष-दर-वर्ष 10.1% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह मजबूत भर्ती गति को दर्शाती है। इस वृद्धि का नेतृत्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) और मशीन लर्निंग (एमएल) भूमिकाओं में 61% की उछाल ने किया।

नई भर्ती में 15% की वृद्धि दर्ज हुई। यह शुरुआती करियर अवसरों के विस्तार और भारत के बदलते नौकरी बाजार में नई-पीढ़ी के कौशलों की बढ़ती मांग को दर्शाती है।

बीमा, आतिथ्य और रियल एस्टेट जैसे गैर-आईटी क्षेत्रों में भी मांग में वृद्धि देखी गई।

रोजगार में आए ये सकारात्मक रुझान बढ़ती आय, मजबूत नौकरी सुरक्षा और बेहतर नौकरी गुणवत्ता को दर्शाते हैं। यह आर्थिक विकास और नीतिगत उपायों के सकारात्मक प्रभाव को प्रतिबिंबित करते हैं। ये संकेतक सामूहिक रूप से अधिक समावेशी रोजगार वृद्धि को दर्शाते हैं। यह उत्पादकता बढ़ाने और सतत आर्थिक विस्तार को समर्थन देते हैं।

सरकारी पहलों से श्रम बाज़ार में बेहतर परिणाम

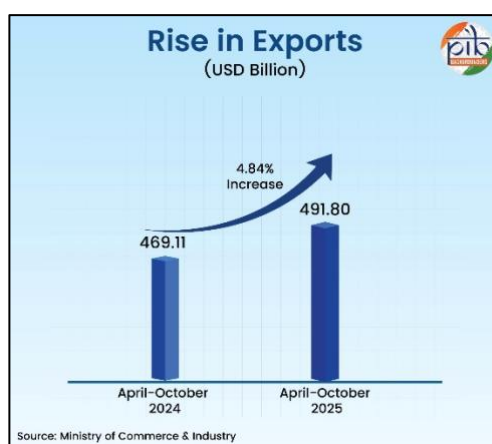
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत 17 नवंबर 2025 तक देशभर में 27 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया गया है। एन ए वी वाई ए (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) उन्हें उभरते क्षेत्रों में रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए उद्योग-संबंधी कौशल प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) इसके अंतर्गत मार्च 2025 तक ₹4,91,406 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, स्टैंड-अप इंडिया जिसके अंतर्गत जून 2025 तक ₹62,790 करोड़ स्वीकृत किए गए और स्टार्ट-अप इंडिया के अंतर्गत 18 नवंबर 2025 तक 2,00,235 डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। ये सभी कार्यक्रम उद्यमिता को

बढ़ावा देते हैं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को विस्तृत करते हैं और श्रम बल के लिए रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य देश की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर व्यक्तित्व विकास तक अनेक कौशल-संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। देशभर के 40 स्थानों पर 17वां रोजगार मेला भी आयोजित किया गया। इसमें 24 अक्टूबर 2025 को 51 हजार से अधिक नव-चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये सभी प्रयास सामूहिक रूप से कौशल को मजबूत करते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और एक सक्षम एवं सुदृढ़ कार्यबल तैयार करते हैं जो समावेशी आर्थिक विकास को गति देता है।

व्यापार प्रदर्शन में सुधार

अप्रैल-अक्टूबर 2025 में भारत का व्यापार क्षेत्र मजबूत बना रहा। यह वैश्विक मांग में वृद्धि और प्रमुख निर्यात श्रेणियों में स्थिर सुधार को दर्शाता है। माल और सेवाओं दोनों के निर्यात में स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई। इससे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अर्थव्यवस्था की दृढ़ता प्रदर्शित हुई।

अप्रैल-अक्टूबर 2025 में भारत के कुल निर्यात (माल और सेवाएं) में 4.84% की वृद्धि हुई और यह 491.80 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 469.11 अरब डॉलर से अधिक है।



माल निर्यात में 0.63% की वृद्धि हुई और यह 254.25 अरब डॉलर रहा। यह वृद्धि वैश्विक व्यापार व्यवधानों के बावजूद स्पेन (40.74%), चीन (24.77%), हांगकांग (20.7%), अमेरिका (10.15%) और यूएई (5.88%) जैसे प्रमुख बाजारों से मजबूत मांग के कारण हुई।

वृद्धि में निम्नलिखित क्षेत्रों का योगदान रहा:

- समुद्री उत्पाद - 16.18%
- मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद - 23.97%
- अन्य अनाज - 25.52%
- काजू - 28.32%
- इलेक्ट्रॉनिक सामान - 37.82%

सेवाओं का निर्यात दृढ़ता का मुख्य स्तंभ बना रहा और अप्रैल-अक्टूबर 2024 के 216.45 अरब डॉलर की तुलना में 9.75% बढ़कर अनुमानित 237.55 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह कंप्यूटर सेवाओं और व्यवसाय सेवाओं में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।

कुल मिलाकर निर्यात क्षेत्र भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास क्षमता को मजबूत कर रहा है।

व्यापार विस्तार में सरकार का समर्थन

भारत सरकार और आरबीआई ने कई योजनाओं और राहत उपायों के माध्यम से व्यापार इकोसिस्टम को मजबूत किया है। प्रमुख उपायों में भारत से निर्यातित माल/सॉफ्टवेयर/सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य की प्राप्ति और प्रत्यावर्तन की अवधि 9 महीने से बढ़ाकर 15 महीने करना शामिल है। इसके अलावा अग्रिम भुगतान प्राप्त होने की तारीख से माल की शिपमेंट अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया है।

कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पात्र निर्यातकों और एमएसएमई को 20 हजार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए 100% गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। यह योजना वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नए एवं उभरते बाजारों में विविधीकरण को समर्थन देने के उद्देश्य से लाई गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक कुल ₹25,060 करोड़ के प्रावधान के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल-चालित ढांचा प्रदान करेगा।

विदेश व्यापार नीति 2023, आर ओ डी टी ई पी प्रतिपूर्ति, जिला-स्तरीय निर्यात हब, और ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट योजना जैसी नीतियाँ बाजार विविधीकरण, बेहतर अनुपालन और सुगम लॉजिस्टिक्स को सक्षम कर रही हैं। इसके साथ ही, विशेष आर्थिक क्षेत्र भी रोजगार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। इन सभी कदमों से निर्यातकों को वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने में मदद मिल रही है और भारत की व्यापार क्षमता का विस्तार हो रहा है।

जीएसटी 2.0 की सफलता

सरकार ने GST (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) में बड़े सुधार शुरू किए, जिसमें 5% और 18% के आसान दो-स्लैब स्ट्रक्चर के साथ रेट को आसान बनाया गया। इस सुधार में खास सेक्टर में रेट में बड़े पैमाने पर कमी की गई है, जिसमें आम आदमी के सामान, ज्यादा मेहनत वाले उद्योग, खेती और हेल्थकेयर पर ध्यान दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था के ज़रूरी ड्राइवर हैं।

अक्टूबर 2025 में ग्राँस जीएसटी कलेक्शन ₹1.96 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी महीने में रिकॉर्ड किए गए ₹1.87 लाख करोड़ से 4.6% ज्यादा है। रेट में रेशनलाइज़ेशन की शुरुआत के साथ रेवेन्यू में यह बढ़ोतरी, त्योहारों के मौसम में मजबूत कंजम्प्शन ट्रेंड को दिखाती है।

GST रेट में कमी से सामान और सर्विस की कीमत कम हुई है, जिससे घरों की बचत और खपत बढ़ी है, और टैक्स बेस भी बढ़ा है। साथ ही, बड़ा टैक्स बेस स्टेबल रेवेन्यू ट्रेंड में मदद कर रहा है, जिससे ज्यादा बैलेंस्ड और सतत विकास का माहौल बन रहा है।

भारत का विकास अनुमान

भारत का ग्रोथ आउटलुक लगातार मजबूत हो रहा है, बड़े ग्लोबल और घरेलू इंस्टीट्यूशन अर्थव्यवस्था की मजबूती और बढ़ती घरेलू डिमांड को देखते हुए अपने अनुमान बढ़ा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वित्त वर्ष 2025-26 सकल घरेलू उत्पाद अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है, जो सभी सेक्टर में मजबूत गति को दिखाता है। इंटरनेशनल एजेंसियां भी इसी उम्मीद को दोहरा रही हैं।

- विश्व बैंक ने मजबूत खपत और जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभावों का हवाला देते हुए 2026 में 6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया है;
- मूडीज को उम्मीद है कि भारत 2026 तक 6.4% और 2027 में 6.5% की विकास दर के साथ बढ़ती हुई जी20 अर्थव्यवस्था बना रहेगा;
- IMF ने 2025 के लिए अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.6% और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है।
- OECD ने 2025 के लिए ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.7% और 2026 के लिए 6.2% कर दिया है।
- S & P का अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद वित्त वर्ष 2026 में 6.5% और 2027 में 6.7% बढ़ेगा।

कुल मिलाकर, ये बदलाव भारत के आर्थिक बुनियादी बातों और बदलती ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद मजबूत, घरेलू विकास बनाए रखने की उसकी क्षमता पर बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल भरोसे को दिखाते हैं।

निष्कर्ष

भारत की अर्थव्यवस्था एक स्थिर और मजबूत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिसे संरचनात्मक सुधार, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी विकास पर जोर देने से मदद मिल रही है। भारत के विकास की राह पर इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के भरोसे और स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक इंडिकेटर के साथ, इकॉनमी अपनी इकॉनॉमिक रफ्तार बनाए रखने के लिए अच्छी स्थिति में है। RBI की महंगाई पर लगातार नज़र रखने और हाल के पॉलिसी उपायों – जैसे कि आसान टैक्स स्ट्रक्चर, लेबर-सेंट्रिक रिफॉर्म और ट्रेड-प्रमोशन पहल – के साथ सरकार की गवर्नेंस की कोशिशें कम्प्लायंस को आसान बनाने, लागत कम करने और सभी सेक्टर में ज्यादा भागीदारी को सपोर्ट करने में मदद कर रही हैं। कुल मिलाकर, ये डेवलपमेंट एक ज्यादा प्रोडक्टिव, कॉम्पिटिटिव और लोगों पर केंद्रित अर्थव्यवस्था की ओर लगातार तरक्की दिखाते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले सतत विकास के साथ जुड़ी हुई है।

संदर्भ-

World Bank

<https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>
<https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/71109bfe-cb0e-47d6-b2c5-722341e42b99/content>

Ministry of Statistics & Programme Implementation

https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/GDP_PR_Q1_2025-26_29082025.pdf
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189186>
<https://mospi.gov.in/54-index-industrial-production>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183312>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2188343>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2190790>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2190829>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2178447>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2195851®=3&lang=1>

RBI

<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MPR011020257F52BDBF1F184AE0A627BD9CEB1580FB.PDF>
[https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/FEMA23\(R\)\(7\)13112025.pdf](https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/FEMA23(R)(7)13112025.pdf)
http://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=61626

Ministry of Commerce & Industry

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189914>
<https://www.startupindia.gov.in/>

Ministry of Road Transport & Highways

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2176932®=1&lang=42>

Department of Economic Affairs

https://dea.gov.in/files/monthly_economic_report_documents/Final-MER%20September%202025.pdf

Department of Financial Services

<https://dfs.dashboard.nic.in/DashboardF.aspx>

Skill India Mission

<https://skillindiamission.in/>
<https://www.skillindiadigital.gov.in/pmkvy-dashboard>

Cabinet

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189389>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2189381>

Ministry of Finance

<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=2163555>
<https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf>

Moodys

<https://www.moodys.com/web/en/us/insights/credit-risk/outlooks/macroeconomics-2026.html>

IMF

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/IND?zoom=IND&highlight=IND

OECD

https://www.oecd.org/en/publications/2025/09/oecd-economic-outlook-interim-report-september-2025_ae3d418b.html

PIB Backgrounder

<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=155121&ModuleId=3#:~:text=Notably%2C%20India%20is%20projected%20to,projected%20GDP%20of%20%247.3%20trillion>
<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=155082&ModuleId=3®=1&lang=42>
<https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NotelId=154880&ModuleId=3>
<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150446>
<https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=150328>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172356>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168711>
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2175702>

News On Air

<https://www.newsonair.gov.in/india-will-become-the-worlds-third-largest-economy-soon-rbi-governor/>

<https://www.newsonair.gov.in/india-remains-fastest-growing-economy-for-4-years-aims-for-20-more-piyush-goyal/>

Ministry of Labour & Employment

https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/EPFO_PRESS_RELEASES/22062025_EPFOAdds19.14LakhNetMembers_April2025.pdf

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2169975>

Prime Minister's Office

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2182117>

Ministry of Electronics and Information Technology

<https://www.meity.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/production-linked-incentive-scheme-pli-for-large-scale-electronics-manufacturing-gNyMDOtQWa>

S&P

<https://www.spglobal.com/en/research-insights/special-reports/india-forward/shifting-horizons/how-indian-economic-growth-realigns-with-shifting-global-tre>

पीके/केसी/आरकेजे/एसके/एनकेएस/एमकेएस